G20

भारत 2023 INDIA

जी20 प्रवेशिका

जी20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के लिए तैयार किया गया पृष्ठभूमि नोट

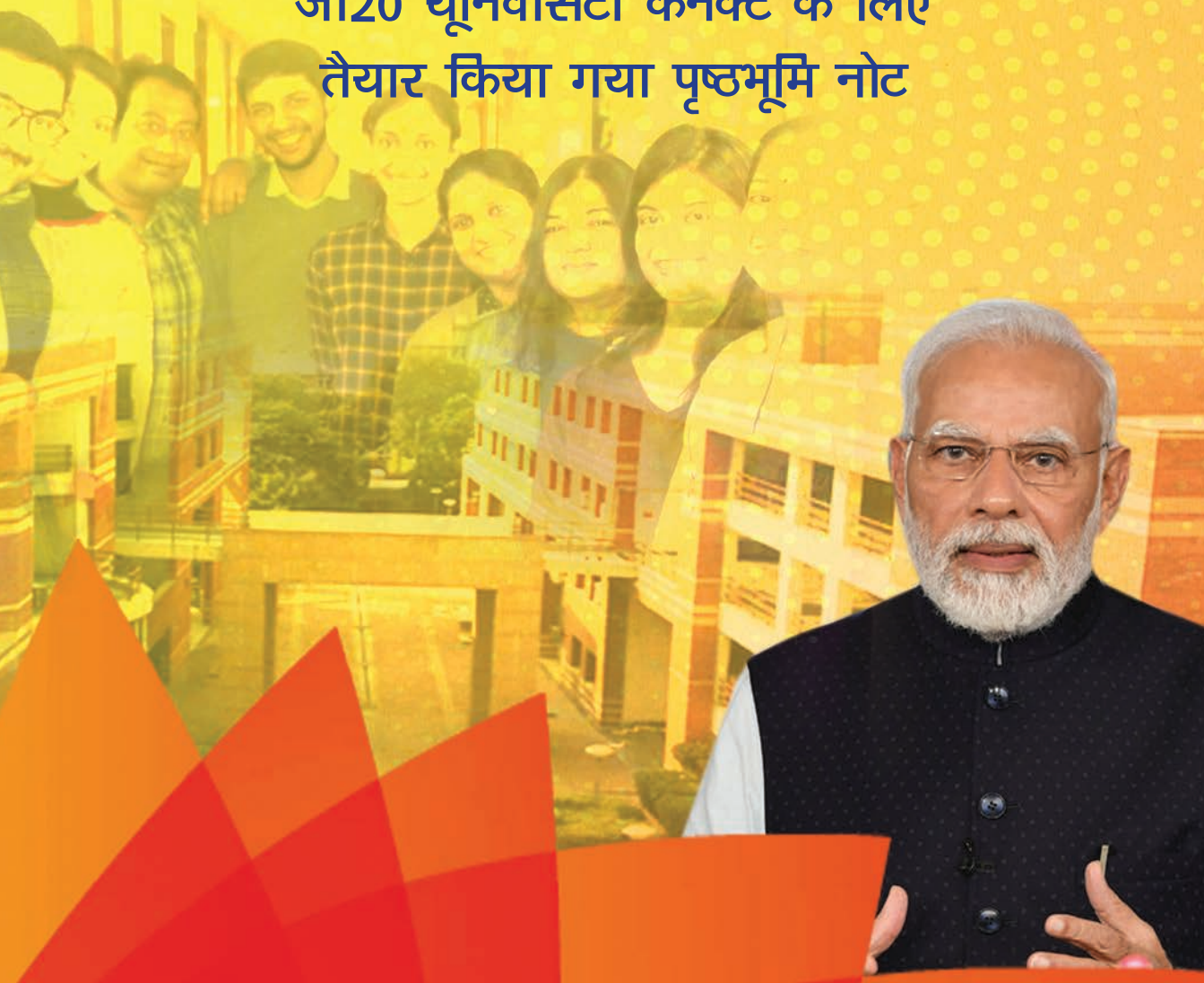

वसुधैव कुटुम्बकम् | ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

आभारोक्ति

'जी20 प्रवेशिका' आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के समग्र मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इस दस्तावेज के लिए महत्वपूर्ण जानकारी श्री मनीष चांद, टीजीआईआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली और आरआईएस टीम ने उपलब्ध कराई है, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रियदर्शी दाश, फेलो डॉ. दुर्गेश राय, परामर्शदाता डॉ. राहुल रंजन और परामर्शदाता डॉ. सयानतन घोशाल शामिल हैं।

हम जी20 शेरपा, श्री अमिताभ कांत; मुख्य समन्वयक (जी20), श्री हर्ष वर्धन श्रृंगला; ओएसडी (जी20), श्री मुक्तेश परदेशी; अपर सचिव और सूस–शेरपा (जी20), श्री अभय ठाकुर और संयुक्त सचिव (नीति योजना और अनुसंधान), विदेश मंत्रालय, डॉ. सुमित सेठ का भी उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।

रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था आरआईएस की प्रकाशन टीम द्वारा की गई, जिसमें श्री तीश मल्होत्रा, प्रकाशन अधिकारी, श्री सचिन सिंघल और श्री संजीव कर्ण, प्रकाशन सहायक शामिल थे।

कॉपीराइट © आरआईएस, 2022

आरआईएस द्वारा 2022 में प्रकाशित

इंडिया@जी20
आशा, सद्भाव और शांति की अध्यक्षता

आशा, सद्भाव, शांति और स्थायित्व–ये वे महत्वपूर्ण विचार हैं, जो दुनिया की सबसे उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी20 की भारत की अध्यक्षता को निर्धारित करेंगे। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था–भारत को जी20 बढ़ते ध्रुवीकरण और गहराते भू–राजनीतिक तनाव के दौर में वैश्विक एजेंडे को आकार देने का महान अवसर प्रदान कर रहा है, ताकि इस बंटी हुई दुनिया में शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि को आगे बढ़ाया जा सके।

समावेशी एवं कार्रवाई–उन्मुख

इंडोनेशिया के बाली द्वीप रिसॉर्ट में 16 नवंबर 2022 को जी20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से जी20 की अध्यक्षता का दायित्व सौंपा। आधिकारिक तौर पर भारत ने साल भर के लिए जी20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को ग्रहण की, जो 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। बाली में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को भारत की जी20 की अध्यक्षता के "समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई–उन्मुख" रहने का आश्वासन देते हुए उसका स्वरूप निर्धारित कर दिया। भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रमुख विषयों और प्राथमिकताओं का सारांश प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि जी20 को शांति और सद्भाव के पक्ष में एक मजबूत संदेश देना होगा और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शांति और सुरक्षा के बिना, "भावी पीढ़ियां आर्थिक विकास या तकनीकी नवाचार का लाभ नहीं उठा पाएंगी।"

जी20 प्रतीक चिन्हः खिलता फूल, सात पंखुड़ियां

भारत की जी20 की अध्यक्षता का सार "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" की थीम में सन्निहित है और जिसे प्राचीन संस्कृत लोकाचार में "वसुधैव कुटुम्बकम" के रूप में व्यक्त किया गया है। इस लोगो में खिलता हुआ कमल और उसकी सात पंखुड़ियों पर विश्व को दर्शाया गया है, जो जीवन के सभी मूल्यों–मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्मजीव – तथा पृथ्वी ग्रह और व्यापक ब्रह्मांड में उनकी परस्पर संबद्धता की पुष्टि करता है। 8 नवंबर 2022 को लोगो लॉन्च किए जाने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जी–20 के लोगो में कमल का प्रतीक इस दौर में आशा का प्रतिनिधित्व करता है।" लोगो लॉन्च किए जाने के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, ''कमल की सात पंखुड़ियां विश्व के सात महाद्वीपों और संगीत के सात सुरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जी20 दुनिया को सद्भाव सहित एक साथ लाएगा। इस लोगो में कमल का फूल भारत की पौराणिक विरासत, हमारे विश्वास, हमारे ज्ञान को दर्शा रहा है।''

भारत के लिए जी20 की अध्यक्षता ''अमृतकाल'' की शुरुआत का भी प्रतीक है। यह ''अमृतकाल'' आजादी की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 से शुरू होकर आजादी के सौवें वर्ष तक की 25 साल की अवधि है और अपने मूल में मानव–केंद्रित दृष्टिकोण के साथ भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज की दिशा में अग्रसर यात्रा है।

प्रमुख प्राथमिकताएं

अपनी जी20 की अध्यक्षता को भारत भू–राजनीतिक तनावों के कारण विकट रूप धारण कर चुके खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे बहु–आयामी संकटों से त्रस्त दुनिया में परिवर्तन और वैश्विक रूपांतरण के उत्प्रेरक के रूप में देखता है। ऐसे दौर में, जहां आम लोगों के जीवन को खतरे में डालते हुए दुनिया संघर्षों में उलझी हुई है, भारत अपनी जी20 अध्यक्षता का उपयोग वैश्विक विकास में नई जान डालने, ठोस जलवायु कार्रवाई और सशक्त वैश्विक स्वास्थ्य संरचना जैसी अनेक चुनौतियों के लिए रचनात्मक और सर्वसम्मति पर आधारित समाधान तैयार करने में करेगा। खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता होगी, क्योंकि महामारी ने लाखों लोगों को गरीबी की खाई में धकेल दिया है। सतत विकास लक्ष्यों की फास्ट–ट्रैकिंग और लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के जरिए दुनिया को पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ जीवन शैली अपनाने की ओर अग्रसर करना, अगले कुछ महीनों की अन्य प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। सूचना प्रौद्योगिकी में अपनी मूलभूत ताकत के साथ, भारत डिजिटल

संरचना को समावेशी बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि यह सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का उत्प्रेरक बन सके। समावोशी विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी।

ध्रुवीकरण के संघर्षों और वैश्विक संस्थानों के कमजोर पड़ने की वजह से विभाजित विश्व में जी20, जो विश्व के 85 प्रतिशत जीडीपी, विश्व के 75 प्रतिषत अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और विश्व की दो–तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। अपनी अध्यक्षता के दौरान, भारत वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग के प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में जी20 की स्थिति और अधिकार को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। आखिरकार, जी20 का जन्म 2008 की वित्तीय मंदी की चरमावस्था के दौरान हुआ था, जिसने दुनिया को विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को शामिल कर एक नया प्रतिनिधित्वपूर्ण बहुपक्षीय समूह स्थापित करने के लिए मजबूर किया था। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया कि विश्व "जी 20 की ओर आशा से" देख रहा है।

अतुल्य भारत

अब से, जी20 'लोकतंत्र की जननी' भारत के लिए अपने समस्त गौरव और विविधता को प्रदर्शित करने का एक अवसर भी होगा, क्योंकि यह आर्थिक प्रगति से लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक, अंतरिक्ष, नवाचार और स्टार्ट–अप तक लगभग हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत 56 विविध स्थानों पर जी20 से संबंधित 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा, जिससे विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को इस जीवंत और वैविध्यपूर्ण देश का दौरा करने का अवसर मिलेगा। जी20 के कार्यक्रम अनेक आगंतुकों के लिए, भारत को अनुभव करने का पहला अवसर होंगे और इसलिए सभी भारतीयों को विश्व का स्वागत करने और उनके साथ एक परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्षित करने की आवश्यकता है। इस प्रवेशिका में भारत की जी20 की अध्यक्षता के अंतर्गत प्रमुख विषयों पर संक्षिप्त विवरण शामिल किए गए हैं, जो अगले 12 महीनों में भारत द्वारा 20 सदस्य देशों वाले इस समूह का नेतृत्व संभालने के दौरान उसके प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों और प्राथमिकताओं से विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को अवगत कराएंगे। हमें उम्मीद है कि भारत विश्व को प्रभावित करने वाले के रूप में अपनी पहचान को दृढ़ बनाएगा तथा अधिक समावेशी और न्यायसंगत दुनिया बनाने की दिशा में प्रयासरत जी20 प्रक्रिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ेगा।

ऊर्जा संक्रमण : पर्यावरण के अनुकूल विश्व को आकार देना

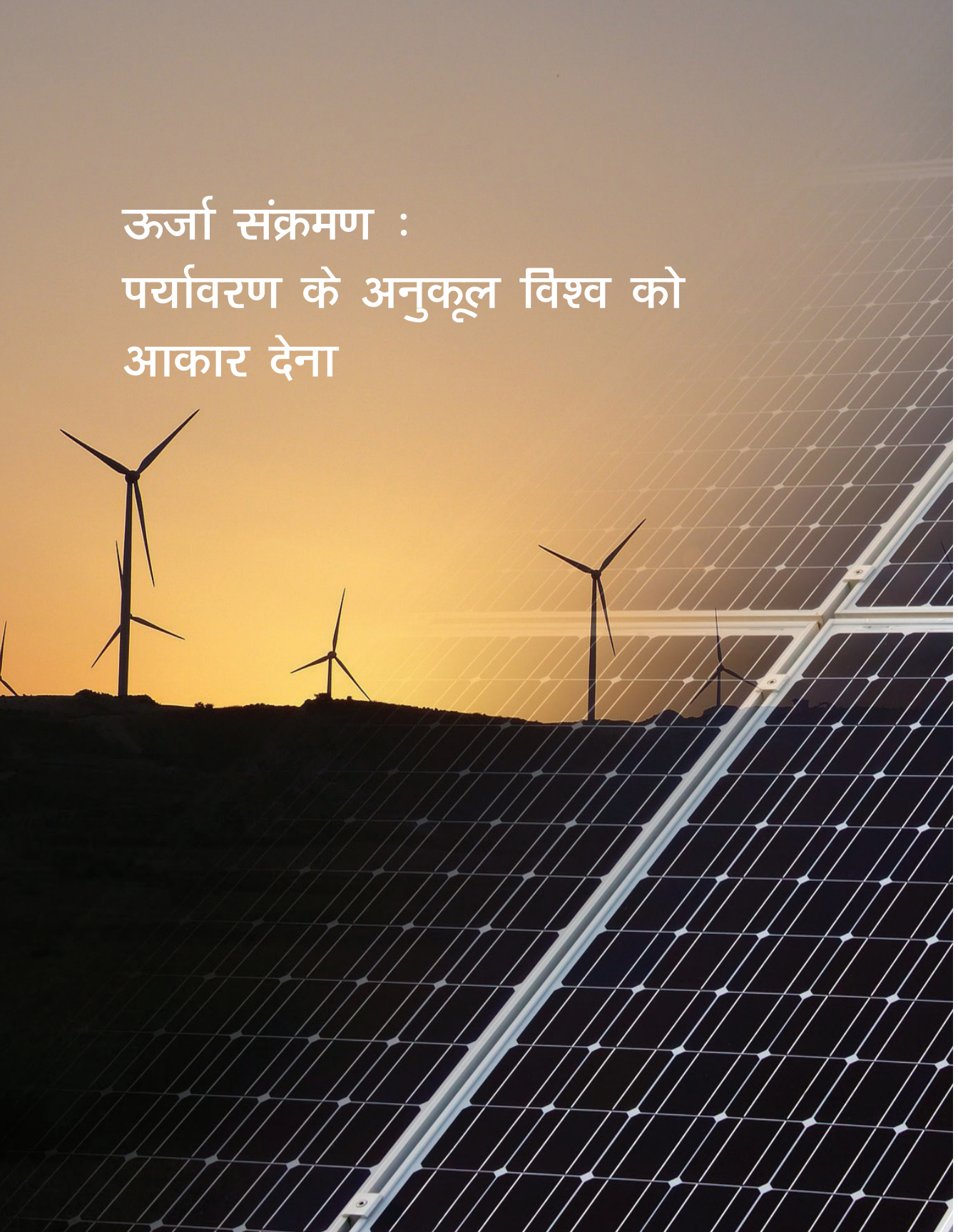

वर्तमान में जारी भारत की नवीकरणीय क्रांति की प्रमुख प्राथमिकता कम कार्बन उत्सर्जन में तेजी लाते हुए ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना है और यह भारत की जी20 की अध्यक्षता के एजेंडा का प्रमुख भाग होगी। नए मानदंड और लक्ष्य निर्धारित करते हुए भारत पहले ही घोषित कर चुका है कि उसकी आधी बिजली नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित की जाएगी। भारत के अनुसार, समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के लिए विकासशील देशों को समयबद्ध और किफायती वित्त तथा प्रौद्योगिकी की सतत आपूर्ति किया जाना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में सीओपी–26 वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में समावेशी ऊर्जा परिवर्तन का अपना विज़न प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने विश्व को "पंचामृतः (पांच अमृत तत्व)" की अवधारणा से अवगत कराया। इस पंच–आयामी योजना में शामिल हैं:

- भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा।
- भारत 2030 तक अपनी 50 प्रतिशत ऊर्जा की जरूरत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करेगा।
- भारत अब से 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करेगा।
- भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।
- भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। यह "पंचामृत" जलवायु कार्रवाई में भारत का अभूतपूर्व योगदान होगा।

"पंचामृत" की यह अवधारणा वर्ष 2022–2023 के दौरान भारत की जी20 की अध्यक्षता के अंतर्गत ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगी। भारत के दृष्टिकोण में, वैश्विक विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यही कारण है कि भारत ऊर्जा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति पर किसी भी प्रतिबंध का विरोध करता है।

सरकार द्वारा देश में ऊर्जा की स्थिति में सुधार के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का अंश बढ़ाने के लिए की गई कई अग्रणी पहलों के कारण भारत द्वारा की जा रही ऊर्जा संक्रमण की हिमायत को अधिक महत्व और विश्वसनीयता हासिल हुई है। भारत ने वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली के हरित स्रोतों को अपनाने की अनुमति देने के लिए नियमों में ढील देकर अपनी जीवाष्म ईंधन से चलने वाली अर्थव्यवस्था में डीकार्बानाइजेशन को गति दी है। भारत फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन नामक वैश्विक पहल में शामिल हो चुका है, जिसका उद्देश्य 30 प्रतिशत वैश्विक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार भारी उद्योग और लंबी दूरी के परिवहन क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज़ करना है।

भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) लॉन्च किया है और 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' की दिशा में काम कर रहा है। 100 से अधिक देश आईएसए में शामिल हो चुके हैं और सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत है, यह गठबंधन एक वैश्विक सौर आंदोलन का रूप ले चुका है।

ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने के लिए, भारत स्वच्छ, टिकाऊ और किफायती ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने और उसे सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा प्रणालियों के परिवर्तन और विविधीकरण का समर्थन करता है। इस संबंध में, भारत विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कमजोर देशों के लिए किफायती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच, क्षमता निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर किफायती नवीनतम प्रौद्योगिकी, पारस्परिक रूप से लाभकारी प्रौद्योगिकीय सहयोग और ऊर्जा क्षेत्र में शमन कार्यों के वित्तपोषण के संदर्भ में निरंतर सहायता दिए जाने की हिमायत करता है।

भविष्य पर गौर करते हुए, भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने तथा उद्योग और ऊर्जा उपभोक्ताओं के व्यापक उपयोग के लिए इसे और किफायती बनाने के लिए आईएसए का लाभ उठाएगा। भारत हरित विकास और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन के संदर्भ में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने पर जोर देगा। भारत के दृष्टिकोण से, सौर ऊर्जा भविष्य की नवीकरणीय ऊर्जा है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को महत्वपूर्ण रूप से कम करने में मदद करेगी। अपनी जी20 की अध्यक्षता के अंतर्गत, भारत वर्तमान में जारी ऊर्जा संक्रमण को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान हस्तांतरण के माध्यम से बढ़ावा देगा। आने वाले दिनों में सौर और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भारत की प्रमुख प्राथमिकता होगी।

गेट अ लाइफः पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना

ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर में हो रहे नुकसान के कारण जलवायु में सचमुच परिवर्तन हुआ है। नदियां सूख रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और दुनिया के अनेक क्षेत्रों के तापमान में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हो रही है, जिसके कारण चारों ओर तकलीफें बहुत बढ़ गई हैं। जलवायु के कारण घटित हो रही बाढ़, अकाल और तूफान जैसी विषम घटनाएं हमारे अस्तित्व को ही खतरे में डाल रही हैं। जलवायु आपातकाल की इस आसन्न पृष्ठभूमि के संदर्भ में, भारत ने टिकाऊ और स्वस्थ जीवन शैली के लिए 'लाइफ'– पर्यावरण के लिए जीवनशैली – नामक स्वदेशी तौर पर विकसित पहल की शुरुआत की है और इसे जी20 सहित वैश्विक एजेंडे में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में 1 नवंबर 2021 को वार्षिक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन सीओपी–26 में यह अवधारणा प्रस्तुत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में विश्व समुदाय से पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए "बिना सोचे समझे और विनाशकारी उपभोग के बजाय, सावधानी से और सोच–समझकर उपयोग करने" की दिशा में एक अंतरराष्ट्रीय जन आंदोलन के रूप में लाइफ का संचालन करने का आह्वान किया।

लाइफ "ग्रह की, ग्रह के लिए और ग्रह द्वारा जीवन शैली" का अनुसरण करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई के केंद्र में व्यक्ति को रखता है। जटिल दीर्घ नीतिगत बहसों तथा सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका से आगे बढ़ते हुए लाइफ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर काबू पाने के लिए कार्यालय या जिम जाने के लिए साइकिल का उपयोग करने जैसे सरल कार्यों से जीवन शैली में बदलाव लाने को प्रोत्साहित करता है। लाइफ इस अंतर्निहित विश्वास से प्रेरित है कि केवल व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार में बदलाव लाकर ही पर्यावरण और जलवायु संकट की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अनुसार, यदि आठ बिलियन वैश्विक आबादी में से एक बिलियन लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाते हैं, तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 20 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। इस नई योजना में ऐसी जीवनशैली अपनाने वालों को लाइफ के अंतर्गत प्रो प्लैनेट पीपल के रूप में मान्यता दी गई है।

टिकाऊ जीवन–शैली को बढ़ावा देने के अपने मिशन में नए प्राण फूंकते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विशाल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए प्रसिद्ध सुंदर गुजराती शहर केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में 'मिशन लाइफ' लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, मिशन लाइफ़ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को लोकतांत्रिक बनाता है, जिसमें सभी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देते हैं। इस बात को रेखांकित करते हुए कि 'मिशन लाइफ' प्रो प्लैनेट पीपल ग्रह की अवधारणा को मजबूत करेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि यह पी–3 मॉडल, यानी प्रो–प्लैनेट पीपल की भावना को मजबूत करेगा।'' भारत की परंपराओं और संस्कृति के अभिन्न अंग पुनः उपयोग करना, कम करना और पुनर्चक्रण करना, मिशन लाइफ का भी हिस्सा हैं, क्योंकि यह लोगों को स्थायी विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है।

लाइफ कार्य योजना में व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण–अनुकूल कार्यों (मांग) का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना, उद्योगों और बाजारों को बदलती मांग के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया (आपूर्ति) करना तथा टिकाऊ खपत और उत्पादन (नीति) दोनों का समर्थन करने के लिए सरकार और औद्योगिक नीति को प्रभावित करना शामिल है।

वैश्विक कल्याण के लिए लाइफ की परिवर्तनकारी क्षमता को देखते हुए, भारत ने जी20 के एजेंडे में टिकाऊ जीवन शैली को शामिल किया है। जी20 वैश्विक जीडीपी के 80 प्रतिशत और साथ ही साथ वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के 80 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए भी उत्तरदायी है। इसलिए भारत की दृष्टि से, जी20, लाइफ को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली का वैश्विक आंदोलन बनाने की दिशा में चाक–चौबंद है। मिशन लाइफ दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में मदद करेगा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टिकाऊ जीवन शैली का नेतृत्व करेगा। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर 2022 को बाली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में लाइफ के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "इस ग्रह के सुरक्षित भविष्य के लिए, ट्रस्टीशिप की भावना ही समाधान है। लाइफ अभियान इसमें प्रमुख योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य टिकाऊ जीवन शैली को एक जन आंदोलन बनाना है।" जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैश्विक बहस में बदलाव लाने के भारत के प्रयासों को मान्यता देते हुए जी20 बाली के नेताओं के घोषणापत्र में सतत विकास और जीवन शैलियों, संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा का समर्थन किया गया है।

भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत, लाइफ को अतिरिक्त बल प्राप्त होगा, क्योंकि इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ–साथ भारत में स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की आकांक्षा रखने वालों का समर्थन प्राप्त होगा। आने वाले महीनों में लाइफ जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में वैश्विक मंत्र बनने की ओर अग्रसर है। मिशन लाइफ़ को विश्व के नेताओं से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जिन्होंने पर्यावरण के अनुकूल बदलाव लाने में "वसुधैव कुटुम्बकम" के अपने आध्यात्मिक आदर्श को सम्मिश्रित करने के लिए भारत की पहल की सराहना की है। भारत की जी20 की अध्यक्षता का आदर्श वाक्य – "एक पृथ्वी एक ग्रह एक भविष्य"–जीवन, ग्रह और लोगों के सार को व्यक्त करता है। मिशन लाइफ नागरिकों और सरकारों से इस ग्रह को बचाने के लिए कदम उठाने का आह्वान करता है।

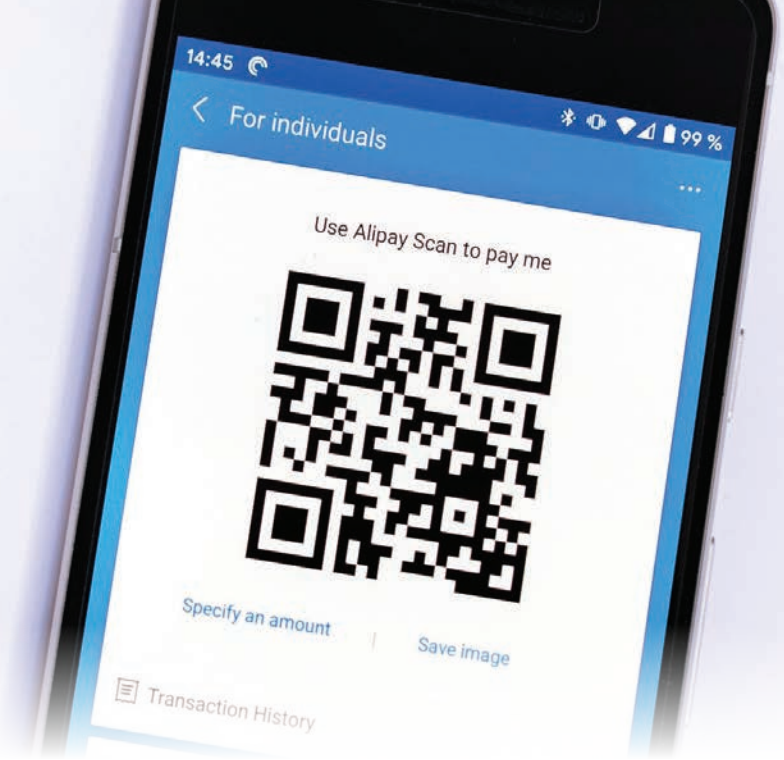

विभेद मिटाना:
डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं

कोविड के बाद की दुनिया में डिजिटल परिवर्तन न्यू नॉर्मल है। कोविड–19 के मद्देनजर, इंटरनेट हमारी कक्षा, हमारे कार्यस्थल, बैठक स्थल और वैचारिक आदान–प्रदान के पसंदीदा मंच के रूप में उभरा है। डिजिटल की परिवर्तनकारी क्षमता को देखते हुए, आने वाले महीनों में भारत की जी20 की अध्यक्षता और राजनयिक आउटरीच का एक प्रमुख फोकस पूरे स्पेक्ट्रम में डिजिटल परिवर्तन को गति देना होगा। इस डिजिटल परिवर्तन में डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल वित्त, डिजिटल सरकार, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल शिक्षा सम्मिलित होंगे।

डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग गरीबी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में, भारत, जहां अब 80 प्रतिशत से अधिक भारतीयों के पास बैंक खाते हैं, जबकि 2014

में लगभग 50 प्रतिशत लोगों के पास ही बैंक खाते हुआ करते थे, अपनी डिजिटल परिवर्तन की कहानी को प्रदर्शित करके मार्ग प्रशस्त कर सकता है, – और इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को विकसित और विकासशील देशों के साथ साझा कर सकता है।

भारत डिजिटल संरचना को समावेशी बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि यह सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन में मददगार बन सके। गवर्नेंस में पारदर्शिता को बढ़ावा देने सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्तर और गति प्राप्त करने के लिए डिजिटल परिवर्तन महत्वपूर्ण है। भारत द्वारा विकसित डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं की संरचना अंतर्निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ सन्निहित है। ये समाधान ओपन सोर्स, ओपन एपीआई, ओपन स्टैंडर्ड्स पर आधारित हैं, जो इंटरऑपरेबल और सार्वजनिक हैं। भारत द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पिछले साल, दुनिया के 40 प्रतिशत से अधिक रीयल–टाइम भुगतान लेन–देन यूपीआई के माध्यम से हुए। इसी प्रकार, डिजिटल पहचान के आधार पर 460 मिलियन नए बैंक खाते खोले गए, जिसकी बदौलत भारत आज वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन गया है। भारत के ओपन सोर्स कोविन प्लेटफॉर्म को मोटे तौर पर मानव इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के रूप में देखा गया है।

"आधार, दीक्षा, स्वयं सार्वजनिक डिजिटल अवसंचरना के कुछ प्रमुख तत्व हैं जिन्हें भारत ने बीते कुछ वर्षों में विकसित किया है। भारत को यूलिप (यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म) को आगे बढ़ाना होगा और वह ओएनडीसी (डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क) के निर्माण की प्रक्रिया में है।

लेकिन जहां एक ओर भारत डिजिटल पहुंच को सार्वजनिक कर रहा है, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर डिजिटल विभेद मौजूद है। दुनिया के अधिकांश विकासशील देशों के नागरिकों के पास किसी तरह की डिजिटल पहचान नहीं है। केवल 50 देशों में डिजिटल भुगतान प्रणालियां हैं। इस संदर्भ में, भारत हर इंसान के जीवन में डिजिटल परिवर्तन लाने पर जोर देगा, ताकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभ से वंचित न रहे। बाली में जी20 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताया कि अपनी जी20 की अध्यक्षता के दौरान भारत इस उद्देश्य के लिए जी20 साझेदारों के साथ संयुक्त रूप से काम करेगा। "विकास के लिए डेटा" का सिद्धांत हमारी अध्यक्षता की समग्र थीम "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" का अभिन्न अंग होगा।

भारत गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के संबंध में डिजिटल परिवर्तन को सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की कुंजी के रूप में देखता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजिटल परिवर्तन के लाभ कहीं मानव जाति के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित न रह जाएं, भारत अन्य जी20 देशों के साथ भी मिलकर कार्य करेगा।

भविष्य में, डिजिटल और पर्यावरण के अनुकूल ढलना बड़े अवसर हैं। भारत के जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने कहा, "400 मिलियन लोग ऐसे हैं, जिनकी कोई डिजिटल पहचान नहीं है; 20 करोड़ लोगों के पास बैंक खाता नहीं है; क्योंकि लगभग 133 देशों में त्वरित भुगतान तक भी नहीं है। ऐसे में दुनिया को बदलने के लिए इसे उपयोग में लाने का यह एक बड़ा अवसर है।"

जलवायु वित्तः पर्यावरण के अनुकूल विकास के लिए वित्तीय सहायता

जलवायु वित्त हरित परिवर्तन और पर्यावरण के अनुकूल विकास की रफ्तार में तेजी लाने का मूलमंत्र है। ग्लोबल वॉर्मिंग के हानिकारक परिणामों के प्रति दुनिया की उत्तरोत्तर सतर्कता के साथ ही विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों को जलवायु वित्त की समयबद्ध तत्काल सुपुर्दगी अत्यावश्यक हो चुकी है। भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जलवायु वित्त के लिए लगातार आवाज उठाता आया है, क्योंकि वह बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए ऐतिहासिक रूप से विकसित देशों को जिम्मेदार मानता है। इसी तर्क के आधार पर, अन्य विकासशील देशों के साथ, भारत ने हरित परिवर्तन के लिए वित्तीय मदद हेतु जलवायु वित्त में तेजी लाने को जी20 में एक ठोस मुद्दा बनाया है। कोपेनहेगन में 2009 में आयोजित वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन सीओपी15 में विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्श 2020 तक संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर की राशि एकत्र करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। लेकिन 14 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह लक्ष्य आंशिक रूप से हासिल किया गया है।

इसी पृष्ठभूमि में, जलवायु वित्त की सुपुर्दगी में तेजी लाना और जलवायु वित्त के लिए महत्वाकांक्षा बढ़ाना भारत की जी20 की अध्यक्षता के दौरान सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। भारत के दृष्टिकोण में, अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर की राशि में से जलवायु वित्त में पर्याप्त वृद्धि

किए जाने और समृद्ध देशों को संसाधन जुटाने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में, नवंबर, 2022 में बाली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों को जलवायु वित्त की सुपुर्दगी में तेजी लाने पर सहमति प्रकट की गई थी। साथ ही विकासशील देशों की सहायता के लिए प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर की राशि से महत्वाकांक्षी नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) पर काम करने पर भी सहमति बनी थी।

अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत, विकसित देशों को जलवायु वित्त के लिए प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर की पूंजी में वृद्धि करने के लिए राजी करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा सहित बिजली के उत्पादन के दौरान शून्य और कम उत्सर्जन का नियोजन बढ़ाने के लिए भारत जी20 देशों के साथ मिलकर काम करेगा। भारत में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान, तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को मजबूती प्रदान किए जाने की संभावना है।

भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए कामयाबी के तौर पर, बाली घोषणापत्र में शमन और अनुकूलन में संतुलन कायम करने के संदर्भ में विकसित देशों से, विकासशील देशों के अनुकूलन हेतु जलवायु वित्त के सामूहिक प्रावधान को वर्ष 2025 तक, वर्ष 2019 के स्तरों से कम से कम दो गुना करने का अनुरोध किया गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में भारत समृद्ध देशों से जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निर्धन और विकासशील देशों की क्षमता को मजबूत बनाने के संदर्भ में ठोस कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा रखता है।

जलवायु संकट की विकटता को देखते हुए कार्रवाई करने में अब और देरी नहीं की जा सकती। इस संदर्भ में, जी20 की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह विकसित देशों को जलवायु वित्त के संबंध में ठोस कदम उठाने के लिए राजी करे। अपनी अध्यक्षता के दौरान, भारत विकसित देशों पर दबाव बनाएगा कि वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करें। भारत के दृष्टिकोण में, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को देखते हुए, विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संसाधन जुटाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिए। अनुकूलन और शमन परियोजनाओं के बीच धन का न्यायोचित आवंटन होना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा, मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने के लिए जी20 सहयोग को व्यापक बनाना

कोविड–19 महामारी और रूस–यूक्रेन संकट के बाद आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई रुकावटों के मद्देनजर, खाद्य असुरक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का मुख्य विषय बन चुकी है और भारत की जी20 की अध्यक्षता के एजेंडे में इसको प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। चूंकि खाद्य संकट विकासशील और विकसित दोनों तरह के ही देशों को प्रभावित करता है, ऐसे में भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए उत्तर के धनी देशों और दक्षिण के गरीब देशों, दोनों के ही लिए ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहायता बढ़ाने में अपनी जी20 की अध्यक्षता का उपयोग करेगा। इस संबंध में, भारत न केवल अपने 1.3 बिलियन नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की मजबूत पहचान रखता है, बल्कि वह कई विकासशील देशों के लिए खाद्य प्रदाता के रूप में भी उभरा है। दक्षिणीय सहयोग की भावना से, भारत ने अन्य देशों के साथ ही साथ अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं तथा कई बार दवाओं और टीकों की खेप भेजी, ईंधन, आवश्यक वस्तुओं और ट्रेड सेटलमेंट के लिए श्रीलंका को 3.8 बिलियन

डॉलर का ऋण दिया, म्यांमार को 10,000 मीट्रिक टन की खाद्य सहायता और टीकों की खेप की आपूर्ति की।

महामारी और रूस–यूक्रेन संकट की दोहरी मार के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के ध्वस्त हो जाने को देखते हुए भारत अपनी जी20 की अध्यक्षता के दौरान खाद और खाद्यान्न दोनों की आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर और सुनिश्चित बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संघटित करेगा। भारत विशेष रूप से उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति को प्राथमिकता देगा। बाली में 15–16 नवंबर 2022 को आयोजित जी –20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "वर्तमान की उर्वरकों की कमी, भविष्य का खाद्य संकट है, जिसका दुनिया के पास कोई समाधान नहीं होगा।"

वैश्विक खाद्य संकट से राहत पहुंचाने के लिए भारत ने विश्व बाजारों में रूसी खाद्य उत्पादों और उर्वरकों की आपूर्ति के लिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का समर्थन किया है। इससे तनाव को कम करने और विकासशील देशों में वैश्विक खाद्य असुरक्षा और भूख की रोकथाम करने के लिए यूक्रेन और रूस से अनाज, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों/इनपुट की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इस संबंध में, भारत निर्यात पर रोक या खाद्य और उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ है।

अपनी जी20 की अध्यक्षता के दौरान भारत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को कार्यशील रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को संघटित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत ने सभी जरूरतमंदों, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए खाद्यान्न और खाद्य उत्पादों की पहुंच, सामर्थ्य और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए खाद्य असुरक्षा की समस्या को हल करने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्षित की है।

खाद्य और पोषण सुरक्षा की स्थिति में सुधार लाने के क्रम में कृषि, खाद्य प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी में अधिक तालमेल बनाने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देना भारत की प्रमुख प्राथमिकता होगी।

भविष्य पर गौर करते हुए भारत सतत खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में जलवायु–अनुकूल और स्मार्ट कृषि भारत के अंतरराष्ट्रीय सहयोग की एक प्रमुख विशेषता होगी। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत मोटे अनाजों जैसे पौष्टिक और पारंपरिक खाद्यान्नों को भी फिर से लोकप्रिय बनाएगा। इस संदर्भ में भारत अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाने के लिए अपनी अध्यक्षता में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।

खाद्य सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है और इस कारण विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए जी20 देशों का समर्थन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागरिक–केंद्रित पहल "वन नेशन वन राशन कार्ड योजना" की शुरूआत की है।

खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा पहल सहित अनेक प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान किए जाने वाले नियमित मासिक खाद्यान्न के अतिरिक्त था। इस योजना ने कोरोना महामारी के चरम के दौरान 800 मिलियन से अधिक भारतीयों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की। आईएमएफ ने भारत में गरीबी के स्तर में अत्यधिक वृद्धि को रोकने की दिशा में इस योजना की सराहना की है और इस बात को रेखांकित किया है कि दोगुना खाद्य सहायता मिलने से गरीबों को कोविड के कारण उनकी आमदनी घटने की समस्या से निपटने में काफी मदद मिली।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय आउटरीच के संदर्भ में, भारत के पास जी20 देशों की तुलना में विशाल कृषि जनशक्ति है, जिसका उपयोग खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय कृषि प्रतिभा वैश्विक खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारतीय कृषि कौशलों ने दुनिया के कुछ देशों में पनीर और जैतून जैसे पारंपरिक कृषि उत्पादों को नया जीवन देने में मदद की है।

जैसे–जैसे डिजिटल प्रौद्योगिकियों में और अधिक उन्नति हो रही है और कृषि–प्रौद्योगिकी कंपनियां उभर रही हैं, भारत के पास शून्य–जुताई खेती तकनीक, सटीक खेती, अनुबंध खेती, ड्रिप सिंचाई जैसी पारंपरिक और कम लागत वाली कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए अपने ज्ञान और तकनीकी जानकारी को साझा करने तथा उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने का अवसर मौजूद है।

भूख और कुपोषण से निपटने के लिए कृषि को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक टिकाऊ बनाने के लिए जी20 के प्रयासों को बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। इस संबंध में, सकारात्मक, पोषण संबंधी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशकों, शाकनाशियों और दूषण से मुक्त विभिन्न कृषि तकनीकों और विधियों को अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

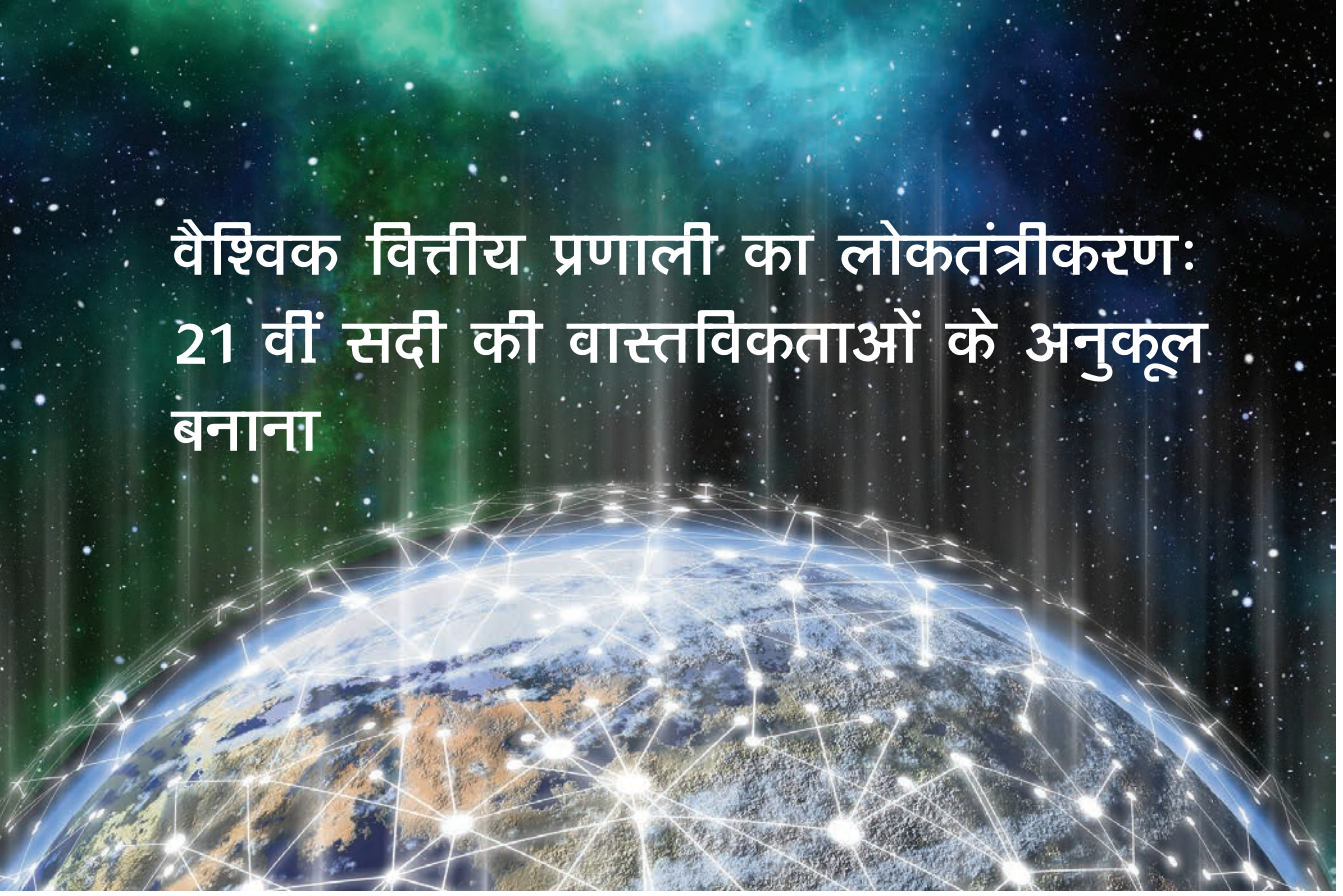

वैश्विक वित्तीय प्रणाली का लोकतंत्रीकरण: 21 वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुकूल बनाना

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित विश्व व्यवस्था तेजी से अप्रचलित और कमजोर पड़ चुकी है। इसने उभरते संकटों से निपटने की वैश्विक संस्थाओं की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस संदर्भ में, वैश्विक वित्तीय प्रणाली से संबद्ध संस्थाओं को अधिक लोकतांत्रिक और विश्व व्यवस्था में जारी बदलावों के मुताबिक प्रतिनिधित्व पर आधारित बनाना जी20 की अपनी अध्यक्षता के अंतर्गत भारत की प्रमुख प्राथमिकता है। विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं पश्चिम का गढ़ बनी हुई हैं और इन्हें प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उभरते और विकासशील देशों को इनमें अधिक प्रतिनिधित्व और महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उदय को देखते हुए विकास बैंकों सहित बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में तत्काल सुधार की आवष्यकता है। इसी पृश्ठभूमि में, वैश्विक शासन प्रणाली से जुड़ी संस्थाओं में तेजी से

सुधार लाना भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक होगा।

यूक्रेन संकट के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं के संकट और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के ध्वस्त हो जाने ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधारों में तेजी लाना और अधिक आवश्यक बना दिया है। बाली में जी20 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से संकट के पैमाने को सामने रखा और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "प्रत्येक देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौती ज्यादा गंभीर है। रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ही उनके लिए संघर्ष थी। उनके पास इस दोहरी मार से निपटने का वित्तीय सामर्थ्य नहीं है। इस दोहरी मार के कारण, उनके पास इसे संभालने के लिए वित्तीय क्षमता का अभाव है।" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमें यह स्वीकारने में भी संकोच नहीं करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं इन मुद्दों पर विफल रही हैं और हम सभी उनमें उपयुक्त सुधार करने में नाकाम रहे हैं।" भारत के दृष्टिकोण में, बेहतर वैश्विक शासन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय संगठनों में सुधार आवश्यक है, ताकि कोविड के पश्चात तेजी से स्थिति बहाल की जा सके।"

वर्तमान में, आईएमएफ और विश्व बैंक की शासन संरचना एक विशेष प्रकार की संचालन संरचना है। वे दोनों बोर्डों द्वारा नियंत्रित हैं, जिनमें मतदान की शक्ति उनके सदस्य देशों के आर्थिक आकार पर निर्भर करती है। इस व्यवस्था के कारण बेहद विषम स्थिति उत्पन्न हुई हैः अमेरिकी सरकार के पास 16 प्रतिशत का वोट शेयर है जबकि 100 मिलियन से अधिक आबादी वाला इथियोपिया जैसा देश – आईएमएफ में केवल 0.09 प्रतिशत वोटों को नियंत्रित करता है। विश्व बैंक का नेतृत्व हमेशा एक अमेरिकी और आईएमएफ का नेतृत्व एक यूरोपीय द्वारा किया जाता रहा है। दोनों संगठनों का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी में है और उनमें उच्च आय वाले देशों के कई अर्थशास्त्री कार्यरत हैं। विकसित देशों के पक्ष वाली इस शासन संरचना में तत्काल बदलाव लाने की जरूरत है।

भारत मजबूत, कोटा–आधारित और पर्याप्त संसाधनों पर केंद्रित आईएमएफ सहित सुदृढ़ और प्रभावी ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाए रखने की प्रतिबद्धता कायम रखे हुए है। भारत मार्गदर्शक के रूप में नए कोटा फॉर्मूला सहित कोटे की 16वीं सामान्य समीक्षा के तहत, 15 दिसंबर, 2023 तक आईएमएफ की संचालन व्यवस्था में

सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जोर देना जारी रखेगा। जी20 देशों द्वारा सतत पूंजीगत प्रवाहों को बढ़ावा देने तथा स्थानीय मौद्रिक पूंजी बाजारों को विकसित करने सहित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना के दीर्घकालिक वित्तीय लचीलेपन की दिशा में कार्य किए जाने की संभावना है।

वैश्विक शासन प्रणाली को संशोधित करने के संबंध में भारत का नजरिया संशोधित बहुपक्षवाद की उस अवधारणा से प्रेरित है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 में लीडर्स रिट्रीट में पहली बार उल्लेख किया था। इसका उद्देश्य समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करने वाली बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधारों पर बल देना और अन्य प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को इस प्रणाली में अपना पक्ष रखने का व्यापक अधिकार देना था। इसी विचार के अनुरूप, भारत जी20 सहित विभिन्न वैश्विक मंचों पर वैश्विक शासन संरचना, आर्थिक और राजनीतिक सुधार की लगातार वकालत करता रहा है। कई मायनों में, जी20 सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला बहुपक्षीय समूह है, जिसमें विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले दोनों ही तरह के देश शामिल हैं और इसलिए यह बहुपक्षीय संस्थाओं और बैंकों के सुधार को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सबसे बेहतर तरीक से तत्पर है। जी20 की अध्यक्षता वर्ष 2025 तक विकासशील देशों के पास यानी–वर्ष 2022 में इंडोनेशिया, वर्ष 2023 में भारत, वर्ष 2024 में ब्राजील और वर्ष 2025 में दक्षिण अफ्रीका के पास रहने के कारण– यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में महत्वपूर्ण बदलाव लाने पर सामूहिक रूप से जोर देने का उपयुक्त अवसर भी है। भारत की जी20 की अध्यक्षता अंतरराष्ट्रीय शासन व्यवस्था से संबद्ध संस्थाओं में ग्लोबल साउथ को बेहतर ढंग से अपना पक्ष रखने को बढ़ावा देने का अनूठा अवसर है।

इस संबंध में, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में निर्भीकता से नवाचार करने की तत्काल आवश्यकता है। इस बात को लेकर सर्वसम्मति बढ़ रही है कि ब्रेटन वुड्स संस्थाएं 21वीं सदी में अब अपने उद्देश्य की पूर्ति तथा नई भू–आर्थिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं की वैधता को बढ़ाना केवल दुनिया के ही नहीं, बल्कि आईएमएफ और विश्व बैंक के प्रमुख शेयरधारकों के भी हित में है।

एसडीजी में तेजी लाना: दुनिया को रहने की बेहतर जगह बनाना

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास एजेंडा 2030 को हासिल करने का समय जैसे–जैसे पास आ रहा है, उसके साथ ही एसडीजी में तेजी लाना अत्यावश्यक हो गया है। दुर्भाग्यवश, कोविड–19, यूक्रेन–रूस युद्ध, असमान आर्थिक विकास और अत्यधिक महंगाई के कारण एसडीजी की प्रगति की रफ्तार धीमी हो गई है। बाली में जी20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जी20 नेताओं से एसडीजी के संबंध में आपात स्थिति को देखते हुए कदम उठाने तथा ग्लोबल साउथ की सरकारों को जलवायु संकट से निपटने, अकाल और भूख की रोकथाम करने, ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने में सहायता करने का आह्वान किया।

इस पृष्ठभूमि में, भारत अपनी जी20 की अध्यक्षता के दौरान एसडीजी की प्रगति में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। एसडीजी में गरीबी, खाद्य और पोषण सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और जलवायु परिवर्तन जैसे परस्पर संबद्ध मुद्दे शामिल हैं।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) या वैश्विक लक्ष्यों में 17 परस्पर संबद्ध लक्ष्य शामिल हैं, जिन्हें "मानव और ग्रह के लिए वर्तमान और भविष्य में शांति और समृद्धि के लिए साझा ब्लूप्रिंट" के रूप में निरुपित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएन–जीए) द्वारा 2015 में एसडीजी की स्थापना की गई थी और इन्हें यूएन–जीए के 2030 एजेंडा नामक संकल्प में शामिल किया गया है। 17 एसडीजी हैं: गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पुरुषों और महिलाओं में समानता, साफ पानी और स्वच्छता, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, असमानता में कमी, टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साझेदारियां।

एसडीजी भारत के विकास के एजेंडे और परस्पर संबद्ध दुनिया में इसके विश्वास का अभिन्न अंग हैं, जैसा कि "वसुधैव कुटुम्बकम" के लोकाचार में निहित है, वह लोकाचार जो भारत की जी20 अध्यक्षता में अनुप्राणित है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 के निरुपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश का राष्ट्रीय विकास एजेंडा काफी हद तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में प्रतिबिंबित है। इस मायने से, एसडीजी को हासिल करने के संबंध में दुनिया की प्रगति काफी हद तक भारत की प्रगति पर निर्भर करती है।

भारत के प्रयासों का मुख्य जोर विशेष रूप से अल्प विकसित देशों (एलडीसी) और लघु द्वीपीय विकासशील देशों (एसआईडीएस) के लिए एसडीजी की वित्तीय सहायता बढ़ाने और उसमें विविधता लाने पर होगा। इस संबंध में, एसडीजी के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर विकासशील देशों के बीच सर्वसम्मति बन रही है। भारत अग्रिम रूप से वित्तीय प्रवाह बढ़ाकर एसडीजी को हासिल करने में तेजी लाने की दिशा में निजी क्षेत्र के लिए बड़ी भूमिका की वकालत करता है। भारत निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए एसडीजी हासिल करने में सहायता प्रदान करने के लिए निजी निवेश जुटाने सहित वित्तीय सहायता के नवीन स्रोतों और उपकरणों के माध्यम से निवेश बढ़ाने का भी समर्थन करता है।

एसडीजी की फास्ट–ट्रैकिंग अनिवार्य हो चुकी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए वर्किंग पेपर के अनुसार, भारत जी20 के देशों में औरों से विशिष्ट रहा है, क्योंकि उसने वर्ष 2015–2019 के दौरान सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है, और निम्न–मध्यम आय वाले देशों की तुलना में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

भविष्य पर गौर करते हुए, अपनी जी20 की अध्यक्षता के दौरान भारत एसडीजी के लिए घरेलू कर राजस्व में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) से संप्रभु (सरकार) उधार में वृद्धि; और ऋण के भारी बोझ वाले कर्जदारों के लिए ऋण के पुनर्गठन जैसे विभिन्न तरीकों से वित्तीय सहायता में वृद्धि करने के लिए उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगा। भारत दीर्घकालिक विकास में सहायता देने तथा इसे टिकाऊ और समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सार्वजनिक निवेश और संरचनात्मक सुधारों पर बल देने, निजी निवेश को बढ़ावा देने तथा बहुपक्षीय व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को मजबूत बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

जी20 बैठकों में भारत अपनी कुछ उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा तथा अन्य देशों के बीच अनुभवों और सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान–प्रदान पर ध्यान केंद्रित करेगा। एसडीजी में तेजी लाना, समावेशी और समृद्ध ग्रह के निर्माण और इसे आकार देने के भारत के दृष्टिकोण का हिस्सा है, ताकि इसे रहने की एक बेहतर जगह बनाया जा सके।

शब्दकोष

एसीटी–ऐक्सेलरेटर: कोविड–19 टूल्स तक पहुंच (एसीटी)–ऐक्सेलरेटर कोविड–19 परीक्षणों, उपचार और टीकों के विकास, निर्माण और उन तक न्यायसंगत पहुंच में तेजी लाने के वैश्विक सहयोग की एक महत्वपूर्ण संरचना है।

अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (एएएए): सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए एएएए एक मजबूत आधार की स्थापना करता है। यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के साथ सभी वित्तीय प्रवाहों और नीतियों को एक सीध में लाकर सतत विकास हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए एक नई वैश्विक संरचना का भी प्रावधान करता है।

कृषि बाजार सूचना प्रणाली (एएमआईएस): कृषि बाजार सूचना प्रणाली (एएमआईएस) खाद्य बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और संकट के समय में अंतरराष्ट्रीय नीतिगत समन्वय को प्रोत्साहन देने का एक अंतर–एजेंसी मंच है। इसकी स्थापना जी20 की फ्रांस की अध्यक्षता के दौरान की गई थी। इस पहल के तहत गेहूं, मक्का, चावल और सोयाबीन जैसी फसलों को शामिल किया गया है।

वैश्विक कृषि–खाद्य मूल्य श्रृंखलाएं: ये खाद्य और फाइबर के उत्पादकों को दुनिया भर के उपभोक्ताओं के साथ जोड़ती हैं और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प के साथ ही साथ भोजन की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने में मदद करती हैं और साथ ही उत्पादकों के लिए आय का सृजन करती हैं।

अंटार्कटिक संधि प्रणाली: अंटार्कटिक संधि प्रणाली, अंटार्कटिक क्षेत्र में देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई जटिल व्यवस्थाओं का समूह है। अंटार्कटिक संधि उस प्रणाली के केंद्र में है, जिस पर 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षर किए गए थे और जिसे 23 जून 1961 को लागू किया गया था।

अंताल्या युवा लक्ष्य: अंताल्या युवा लक्ष्य, 2015 में अंताल्या, तुर्की में जी20 देशों द्वारा सहमत लक्ष्य "श्रम बाजार में वर्ष 2025 तक 15 प्रतिशत तक स्थायी रूप से पीछे छूट जाने के जोखिम वाले युवाओं की अपने देशों में हिस्सेदारी को कम करना" को संदर्भित करता है।

बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस): बीईपीएस करों के भुगतान से बचने के लिए विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच कर नियमों और विनियमों में कमियों और असमानताओं का फायदा उठाने के लिए बहुराष्ट्रीय उद्यमों (एमएनई) द्वारा अपनाई गई कर नियोजन रणनीतियों को संदर्भित करता है।

सर्कुलर इकोनॉमी: सर्कुलर इकोनॉमी में ऐसे बाजार शामिल हैं, जो उत्पादों को फेंकने और नए संसाधनों का दोहन की बजाए, उत्पादों के पुनः उपयोग को प्रोत्साहन देते हैं। इस अर्थव्यवस्था में, कपड़े, स्क्रैप धातु और अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ अर्थव्यवस्था में वापस आ जाते हैं या अधिक कुशलता से उपयोग में लाए जाते हैं।

अफ्रीका के साथ समझौता (सीडब्ल्यूए): जर्मनी की जी20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीका में ढांचागत क्षेत्रों सहित निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीडब्ल्यूए की शुरूआत की गई थी। सीडब्ल्यूए का मुख्य उद्देश्य मैक्रो, व्यापार और वित्तीय संरचनाओं में महत्वपूर्ण सुधार लाकर अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं में निजी निवेश की दिलचस्पी को बढ़ाना है।

कोवैक्स: कोवैक्स एसीटी–ऐक्सेलरेटर का वैक्सीन स्तंभ है। कोवैक्स का उद्देश्य कोविड–19 टीकों के विकास और निर्माण में तेजी लाना तथा दुनिया के हर देश के लिए उनकी उचित और न्यायसंगत पहुंच की गारंटी देना है।

जलवायु वित्त: जलवायु वित्त सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों की ओर से स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाने वाला वित्त पोषण है, जो जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन कार्यों का समर्थन करने की दिशा में प्रयासरत है। उत्सर्जन को रोकने और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल में विकासशील देशों को सहायता देने के लिए विकसित देशों ने जलवायु वित्त के लिए सालाना 100 बिलियन डॉलर की धनराशि जुटाने पर सहमति प्रकट की।

कॉरपोरेट गवर्नेंस: यह नीति निर्माताओं को आर्थिक दक्षता, सतत विकास और वित्तीय स्थिरता में सहायता देने की दृष्टि से कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए कानूनी, नियामक और संस्थागत ढांचे का मूल्यांकन करने और उसमें सुधार करने में मदद करता है।

भ्रष्टाचार के संबंध में अच्छी पद्धतियों का संग्रह: यह भ्रष्टाचार के संबंध में बेहतर गुणवत्तापूर्ण (वैध, विश्वसनीय, कार्रवाई योग्य, आदि) डेटा, भ्रष्टाचार के जोखिम के स्तर और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों की प्रभावशीलता को मापने के लिए भ्रष्टाचार के आकलन के राष्ट्रीय अनुभवों पर केंद्रित है।

कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस): सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों के ऐसे समूह को संदर्भित करता है, जो वैश्विक ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में वैविध्यपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को अवशोषित या कैप्चर करने और उसका इस्तेमाल निर्माण सामग्री (उपयोग) जैसी चीजों को बनाने या उसे सतह के हजारों फुट नीचे (भंडारण) स्थायी रूप से संग्रहीत करने की प्रक्रिया है।

सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस): सीआरएस ऐसे मानक हैं, जिन्हें कर चोरी से निपटने के लिए साझेदार देशों के बीच सूचना के स्वतः आदान–प्रदान के लिए 2014 में ओईसीडी द्वारा विकसित किया गया। यह ऐसे प्रत्येक देश पर लागू है, जिसने सीआरएस के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है और इसे अपने कानून में बदल दिया है।

डेटा गैप्स इनिशिएटिव (डीजीआई): जी20 की ओर से किए गए आंकड़ों की खामियों की पहचान और आंकड़ों के संग्रह को मजबूती प्रदान करने के अनुरोध पर वर्ष 2009 में डेटा गैप्स इनिशिएटिव (डीजीआई) के दो चरण शुरू किए गए थे। डेटा गैप्स इनिशिएटिव का पहला चरण (डीजीआई–1: 2009–15) संकल्पनात्मक संरचनाओं के विकास के साथ–साथ कुछ आंकड़ों के संग्रह और रिपोर्टिंग में वृद्धि पर केंद्रित था। डीजीआई–2 (2015–21) का मुख्य उद्देश्य नीतिगत उपयोग के लिए विश्वसनीय और समयानुकूल आंकड़ों के नियमित संग्रह और प्रसार को लागू करना था।

ऋण सेवा निलंबन पहल (डीएसएसआई): वर्ष 2020 में जी20 द्वारा प्रारंभ की गई डीएसएसआई ने दुनिया के सबसे गरीब देशों को सीमित अवधि के लिए अपने ऋण सेवा अदायगी को निलंबित करने तथा महामारी और उसके परिणामों से निपटने के लिए उन्हें वित्तीय गुंजाइश प्रदान करने की पेशकश की।

आपदा लचीलापन: यह व्यक्तियों, समुदायों, संगठनों और देशों की विकास की दीर्घकालिक संभावनाओं से समझौता किए बिना खतरों, आघातों या तनावों के अनुकूल ढलने और उनसे उबरने की क्षमता है।

आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा : आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के अंतर्गत महत्वपूर्ण इमारतें, सार्वजनिक सामुदायिक सुविधाएं, ट्रांजिट प्रणालियां, दूरसंचार और बिजली प्रणालियां शामिल हैं, जिन्हें बाढ़, भूकंप या जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदा के प्रभाव का सामना करने के लिए युक्तिसंगत रूप से डिजाइन किया गया है।

एम्पॉवर एलायंस: एम्पॉवर निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाकर महिलाओं की अवसरों तक पहुंच को बेहतर बनाना है। यह आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में अड़चन डालने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ): एफएटीएफ एक अंतर–सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखता है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने का काम करता है।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी): एफएसबी एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और उसके बारे में सिफारिशें करता है। एफएसबी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।

खाद्य गठबंधन: खाद्य गठबंधन एक बहु–हितधारक मंच है। इसका उद्देश्य कृषि खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन लाना और उस परिवर्तन की रफ्तार तेज करना तथा जरूरतमंद देशों के लिए गठबंधन और सामूहिक समर्थन बनाना है। यह वैश्विक प्राथमिकताओं जैसे बढ़ती खाद्य असुरक्षा, जलवायु संबंधी आघातों की तीव्रता तथा वैश्विक खाद्य और कृषि के लिए अस्थिरता से निपटने की दिशा में भी काम करता है।

कार्य का भविष्य: कार्य का भविष्य प्रौद्योगिकीय, पीढ़ीगत और सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव से अगले दशक में कार्य करने की शैली में आने वाले बदलावों का वर्णन करता है।

जी20 इनोवेशन लीग: वर्ष 2021 में जी20 की इटली की अध्यक्षता के दौरान प्रारंभ जी20 इनोवेशन लीग, नवाचार और प्रौद्योगिकी में अंतरराष्ट्रीय निवेश का लाभ उठाने का प्रयास करता है और विश्व की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

जी20 वॉटर प्लेटफॉर्म: 2021 में लॉन्च और सऊदी अरब द्वारा कार्यान्वित किया गया जी20 वॉटर प्लेटफॉर्म दुनिया भर में टिकाऊ जल प्रबंधन के संबंध में अनुभवों को साझा करने का एक डिजिटल साधन है।

ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब (जीआई हब): वर्ष 2014 में जी20 द्वारा स्थापित जीआई हब एक गैर–लाभकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य कार्रवाई–उन्मुख कार्यक्रमों के माध्यम से टिकाऊ, लचीला और समावेशी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के कार्य को आगे बढ़ाना है। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ सहयोग करता है और ज्ञान साझा करने के केंद्र के रूप में काम करता है।

वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई): 10 दिसंबर 2010 को सियोल, दक्षिण कोरिया में आधिकारिक तौर पर प्रारंभ किया गया जीपीएफआई जी20 और गैर–जी20 देशों तथा अन्य हितधारकों के लिए एक समावेशी मंच है, जिसका उद्देश्य पीयर लर्निंग, ज्ञान साझा करने, नीतिगत समर्थन और समन्वय के माध्यम से वित्तीय समावेशन के मुद्दे पर काम करना है।

वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं (जीपीजी): जीपीजी वे वस्तुएं या सेवाएं हैं, जिनके लाभ दुनिया के सभी नागरिकों को प्रभावित करते हैं। वे हमारे सहज वातावरण, इतिहास और संस्कृतियों और तकनीकी प्रगति से लेकर मीट्रिक प्रणाली जैसी रोजमर्रा की उपयोगिता प्रणालियों तक, हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती हैं।

अतिरिक्त इस्पात क्षमता पर वैश्विक फोरम(जीएफएसईसी): जीएफएसईसी अतिरिक्त क्षमता की चुनौती पर चर्चा करने और सामूहिक समाधान तलाशने तथा इस्पात क्षेत्र में बाजार का कामकाज बढ़ाने का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। इस वैश्विक मंच का गठन 2016 में जी20 के हांगजोऊ शिखर सम्मेलन में जी20 नेताओं द्वारा किया गया था। यह वैश्विक मंच जी20 के सभी सदस्य देशों और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के इच्छुक सदस्यों के लिए एक खुला मंच है।

ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट (जीएफएसएन): जीएफएसएन को व्यापक रूप से संस्थागत व्यवस्थाओं के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उन देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है, जिन्हें या तो संभावित आघातों से बचने के लिए बीमे की आवश्यकता होती है या संकट के समाधान के लिए धन की आवश्यकता होती है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य संकटकाल में किसी देश को उसकी स्व–वित्तपोषण क्षमता को बहाल करने और उचित शर्तों के माध्यम से अपनी घरेलू नीतिगत की विफलताओं को संशोधित करने में मदद करना है।

हरित वित्त या ग्रीन फाइनेंस: ग्रीन फाइनेंस का आशय उन वित्तीय व्यवस्थाओं से है जो विशिष्ट रूप से पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ या जलवायु परिवर्तन के पहलुओं को अपनाने वाली परियोजनाओं के उपयोग से संबंधित हैं।

ग्रीन रिकवरी: ग्रीन रिकवरी उन नीतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करती है, जो लंबे अर्से तक मानव और ग्रह को लाभान्वित करते रहेंगे। यह आर्थिक विकास और रोजगार सृजन करते हुए देशों को अपने पुनरुद्धार में सक्षम बनाएगी।

आर्थिक और वित्तीय सांख्यिकी पर अंतर–एजेंसी समूह (आईएजी): 2008 में स्थापित, आईएजी की प्रमुख भूमिका वित्तीय क्षेत्र के संबंध में सांख्यिकी और डेटा की खामियों से संबंधित मुद्दों का समन्वय और निगरानी करना है। आईएजी में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी), यूरोस्टेट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश (आईएमएफ), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और विश्व बैंक शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच (आईईएफ): आईईएफ 71 देशों के ऊर्जा मंत्रियों का विश्व का अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें ऊर्जा उत्पादक और उपभोग करने वाले दोनों देश शामिल हैं, और यह ऊर्जा संबंधित मुद्दों पर बातचीत का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच है।

अवैध, गैर–सूचित और अविनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ना: यह एक व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत मछली पकड़ने संबंधी विविध गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अवैध, गैर–सूचित और अविनियमित मछली पकड़ने की गतिविधियां, मछली पकड़ने के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही तरह के नियमों का उल्लंघन करती हैं। आईयूयू मछली पकड़ना एक वैश्विक समस्या है, जो समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र और टिकाऊ मत्स्य पालन के लिए खतरा है।

अंतरराष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला (आईएमईओ): आईएमईओ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित और कार्रवाई–उन्मुख पहल है, जिसका उद्देश्य मीथेन उत्सर्जन में पर्याप्त कमी को प्रेरित करना है।

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच (आईपीबीईएस): आईपीबीईएस जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और उनके अंतर्संबंधों के बारे में वैश्विक स्तर पर ज्ञान का नियमित और समयबद्ध मूल्यांकन करने से संबद्ध है। आईपीबीईएस को जी20 की जापान की अध्यक्षता के अंतर्गत शुरू किया गया था।

जस्ट ट्रांजिशन: जस्ट ट्रांजिशन का आशय अर्थव्यवस्था को इस तरह पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, जो यथासंभव सभी संबंधित लोगों के लिए उचित और समावेशी हो, काम के अच्छे अवसरों का सृजन करे और कोई भी पीछे न छूटे।

मनी मार्केट फंड: मनी मार्केट फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है, जो अत्यधिक लिक्विड, नीयर–टर्म उपकरणों में निवेश करता है। इन उपकरणों में नकदी, नकदी के समकक्ष प्रतिभूतियां, और हाई–क्रेडिट–रेटिंग, अल्पकालिक परिपक्वता वाली ऋण–आधारित प्रतिभूतियां शामिल हैं।

बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी): एमडीबी विकासशील देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण एमडीबी में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु यूरोपीय बैंक (ईबीआरडी), अंतर–अमेरिकी विकास बैंक (आईएडीबी) और अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) शामिल हैं।

गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआई): एनबीएफआई एक वित्तीय संस्था है, जिसके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता और वह जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं कर सकती। हालांकि एनबीएफआई निवेश (सामूहिक और निजी दोनों), रिस्क पूलिंग, वित्तीय परामर्श, ब्रोकरिंग, मनी ट्रांसमिशन और चेक भुनाने जैसी वैकल्पिक वित्तीय सेवाओं को सुगम बनाती हैं।

ओईसीडी वित्तीय कदाचरण निरोधी सम्मेलनः ओईसीडी वित्तीय कदाचरण निरोधी सम्मेलन को अंतरराष्ट्रीय कारोबारी लेनदेन में विदेशी सार्वजनिक अधिकारियों की वित्तीय कदाचरण से निपटने के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी उपकरण है, जो वित्तीय कदाचरण संबंधी लेनदेन (वित्तीय कदाचरण की पेशकश, उसका वादा करने या उसे देने वाला व्यक्ति या संस्था) के "आपूर्ति पक्ष" पर केंद्रित है। सम्मेलन के पक्षकारों के कानूनों के तहत वित्तीय कदाचरण को आपराधिक मामला माना जाता है।

वन हेल्थः वन हेल्थ' मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को संतुलित और अनुकूलित करने से संबंधित एक समेकित, एकीकृत दृष्टिकोण है। यह कोविड–19 महामारी जैसी वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम, पूर्वानुमान, निदान और इससे निपटने की कार्रवाई की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

ओसाका ब्लू ओशन विजनः वर्ष 2019 में जी20 की जापान की अध्यक्षता के तहत अपनाया गया ओसाका ब्लू ओशन विजन, जी20 देशों द्वारा "समग्र जीवन–चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से समुद्री प्लास्टिक कचरे से होने वाले अतिरिक्त प्रदूषण को 2050 तक शून्य तक कम करने" से संबंधित एक स्वैच्छिक प्रतिबद्धता है।

पेरिस समझौताः पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित कानूनी तौर पर बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस समझौते को 12 दिसंबर 2015 को अपनाया गया और 4 नवंबर 2016 को लागू किया गया। इस समझौते का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व–औद्योगिक स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, बल्कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है।

पेरिस क्लबः पेरिस क्लब आधिकारिक ऋणदाता देशों का एक प्रमुख अंतर–सरकारी समूह है। अनौपचारिक प्रकृति वाला यह समूह देनदार देशों के समक्ष आने वाले भुगतान संबंधी मुद्दों के व्यावहारिक समाधान तलाशने का प्रयास करता है।

गरीबी में कमी और विकास ट्रस्ट (पीआरजीटी): आईएमएफ विकास को बढ़ावा देने और गरीबी में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कम आय वाले देशों को पीआरजीटी के माध्यम से रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

अफ्रीका में अवसंरचना विकास कार्यक्रम (पीआईडीए): पीआईडीए का समग्र लक्ष्य एकीकृत क्षेत्रीय और महाद्वीपीय ढांचागत संरचनाओं के नेटवर्क और सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से अफ्रीका में सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा और गरीबी में कमी लाना है। पीआईडीए को अफ्रीका में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी की जी20 की अध्यक्षता के तहत शुरू किया गया था।

क्षेत्रीय वित्तीय व्यवस्थाएं (आरएफए): आरएफए वे तंत्र या समझौते हैं, जिनके माध्यम से देशों के समूह अपने क्षेत्रों में वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का परस्पर संकल्प लेते हैं।

लचीलापन और स्थिरता ट्रस्ट (आरएसटी): आईएमएफ का आरएसटी कम आय वाले और मध्य–आय वाले कमजोर देशों को बाहरी आघातों के प्रति लचीला बनाने और उनका सतत विकास सुनिश्चित करने में सहायता देने तथा भुगतान संतुलन की दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान देने से संबद्ध है।

विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर): एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश (आईएमएफ) द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार को पूर्णता प्रदान करने के लिए बनाई गई अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। एसडीआर का मूल्य दुनिया की पांच प्रमुख मुद्राओं–डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड की बास्केट पर आधारित है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी): एसडीजी को 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। इन्हें वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। ये गरीबी मिटाने, ग्रह की रक्षा करने और 2030 तक सभी लोगों के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई का सार्वभौमिक आह्वान है। एसडीजी 17 हैं, जो एकीकृत हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक क्षेत्र में की गई कार्रवाई अन्य क्षेत्रों के परिणामों को प्रभावित करती है।

सतत वित्त: सतत वित्त एक ऐसी प्रक्रिया है, जो निवेश से जुड़े निर्णय लेते समय पर्यावरणीय, सामाजिक और शासकीय (एसईजी) सरोकारों को ध्यान में रखती है। यह टिकाऊ आर्थिक गतिविधियों और परियोजनाओं में अधिक दीर्घकालिक निवेश का मार्ग प्रशस्त करती है।

खाद्य की हानि और बर्बादी के मापन और न्यूनीकरण पर तकनीकी मंच(टीपीएलएफडब्ल्यू): इसे 2015 में तुर्की की जी20 की अध्यक्षता के दौरान प्रारंभ किया गया था। यह मंच खाद्य की हानि और बर्बादी के मापन, न्यूनीकरण, नीतियों, गठबंधनों, कार्यों और नवीन तकनीकों और दृष्टिकोणों को शामिल कर दुनिया भर में लागू किए वाले सफल मॉडलों के बारे में जानकारी तक पहुंच कायम करने के लिए अन्य संबंधित मंचों के संबंध में प्रवेश द्वार के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करता है।

कुल हानि अवशोषण क्षमता (टीएलएसी)–कुल हानि अवशोषण क्षमता यह सुनिश्चित करने का एक अंतरराष्ट्रीय मानक है कि वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी–एसआईबी) के पास निवेशकों पर नुकसान का बोझ डालने और सरकार द्वारा संकट से उबारने यानी बेलआउट के जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त इक्विटी और बैंकों के कर्जों को माफ करने की सुविधा यानी बेल–इन डेट उपलब्ध है।

यूएनसीएलओएस: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) को 1982 में अपनाया गया था। यह संधि दुनिया के महासागरों और समुद्रों में कानून और व्यवस्था का समग्र शासन स्थापित करती है, जो महासागरों और उनके संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्थापित करता है। यह समुद्र के कानून के विशिष्ट क्षेत्रों के विकास की एक रूपरेखा भी प्रदान करता है।

यूएन–हैबिटेट: संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम (यूएन–हैबिटेट) का उद्देश्य दुनिया भर में सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कस्बों और शहरों को बढ़ावा देना है। यूएन–हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर शहरीकरण और मानव बस्ती से संबंधित सभी मुद्दों का केंद्र बिंदु है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का आशय समस्त लोगों की जरूरत, समय और स्थान के अनुसार, वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए बिना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने से है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और उपशामक देखभाल तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी श्रृंखला को कवर किया जाता है।

यूएनएससी संकल्प 2347: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का संकल्प 2347 मुख्य रूप से आतंकवाद और आतंकवादी समूहों द्वारा सांस्कृतिक संपत्ति को नष्ट करने और लूटने के जानबूझकर किए गए प्रयासों का मुकाबला करने पर केंद्रित है। यह सशस्त्र संघर्ष के व्यापक संदर्भ में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए वैश्विक समुदाय के सामान्य हित और दायित्व पर भी ध्यान देता है।

महिला उद्यमी वित्त पहल (वी–फाई): अक्टूबर 2017 में स्थापित, वी–फाई का मुख्य उद्देश्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर, क्षमता निर्माण कर, नेटवर्क का विस्तार कर, सलाह देकर तथा स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ने के अवसर प्रदान कर महिला उद्यमियों की सहायता करना है।

जी20 व्यापक आर्थिक संकेतक

संकेतक	जी20 (ट्रिलियन डॉलर)		विश्व में हिस्सेदारी (प्रतिशत)		वृद्धि (प्रतिशत) 2010–2021
	2010	2021	2010	2021	
आउटपुट/गतिविधि					
जीडीपी	55.7	70.1*	85.9	85.6	2.3#
मूल्य वर्धित, कृषि	1.9	2.6*	70.2	71.0	3.1#
मूल्य वर्धित, उद्योग	14.3	18.5*	82.9	83.6	2.6#
मूल्य वर्धित, सेवाएं	36.3	45.9*	86.9	86.5	2.4#
जनसंख्या	4.5	4.9	64.9	62.1	0.7
व्यापार					
व्यापारिक निर्यात	11.7	17.1	76.4	76.4	3.5
व्यापारिक आयात	14.5	17.4	78.4	76.9	1.7
कुल व्यापारिक व्यापार	26.1	34.4	77.5	76.7	2.5
सेवाओं का निर्यात	3.2	4.9	79.6	80.7	4.0
सेवाओं का आयात	3.0	4.4	77.2	78.0	3.5
सेवाओं का कुल व्यापार	6.2	9.3	78.4	79.4	3.8
निवेश					
आवक एफडीआई	1.0	1.1	72.7	69.8	0.8
आउटवर्ड एफडीआई	1.1	1.5	77.0	87.6	3.1
डिजिटल अर्थव्यवस्था					
डिजिटली डिलिवरेबल सेवाओं का निर्यात	1.6	3.2	85.6	84.1	6.5
आईसीटी सेवाओं का निर्यात	0.3	0.7	85.2	85.1	9.9

स्रोतः आईएमएफ–डीओटीएस, आईएमएफ–आईएफएस, यूएनसीटीएडी ओईसीडी

नोटः वृद्धि के लिए, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) की गणना 2010–2021 की अवधि के लिए की गई है।

* आंकड़े साल 2020 के हैं। # सीएजीआर की गणना वर्ष 2010–2020 के लिए की गई है।

जी20 कार्य समूह
(भारतीय अध्यक्षता)

शेरपा ट्रैक

- कृषि
- भ्रष्टाचार–निरोधी
- संस्कृति
- डिजिटल अर्थव्यवस्था
- आपदा जोखिम लचीलापन और कमी
- विकास
- शिक्षा
- रोज़गार
- पर्यावरण और जलवायु निरंतरता
- ऊर्जा संक्रमण
- स्वास्थ्य
- व्यापार और निवेश
- पर्यटन

वित्तीय ट्रैक

- फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी)
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए)
- इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप (आईडब्ल्यूजी)
- टिकाऊ वित्तीय कार्य समूह (एसएफडब्ल्यूजी)
- वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी (जीपीएफआई)
- संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल
- अंतर्राष्ट्रीय कराधान एजेंडा
- वित्तीय क्षेत्र की समस्याएं

जी20 कार्य समूह
(भारतीय अध्यक्षता)

- बिजनेस–20 (बी20)
- सिविल–20 (सी–20)
- लेबर–20 (एल–20)
- पार्लियामेंट–20 (पी–20)
- साइंस–20 (एस– 20)
- शीर्ष लेखापरीक्षा संस्थान–20 (एसएआई–20)
- स्टार्टअप–20 (एस–20)
- थिंक–20 (टी–20)
- अर्बन–20 (यू–20)
- वूमन–20 (डब्ल्यू–20)
- यूथ–20 (वाई–20)

जी20 के स्थायी आमंत्रित सदस्य

देश

- स्पेन

अंतरराष्ट्रीय संगठन

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन)
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश (आईएमएफ)
- विश्व बैंक (डब्ल्यूबी)
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)
- वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी)
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)
- अफ्रीकी संघ (एयू)
- अफ्रीकी संघ विकास एजेंसी (एयूडीए–एनईपीएडी)
- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान)

अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन

(भारत की जी20 की अध्यक्षता, 2023)

देश

- बांग्लादेश
- मिस्र
- मॉरीशस
- नीदरलैंड
- नाइजीरिया
- ओमान
- सिंगापुर
- संयुक्त अरब अमीरात

अंतरराष्ट्रीय संगठन

- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)
- आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)
- एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

जी20 सदस्य देश

ऑस्ट्रेलिया

अर्जेंटीना

ब्राजील

कनाडा

चीन

यूरोपीय संघ

फ्रांस

जर्मनी

भारत

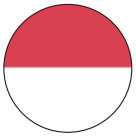
इंडोनेशिया

इटली

जापान

मैक्सिको

रूस

दक्षिण अफ्रीका

सऊदी अरब

दक्षिण कोरिया

तुर्की

अमेरिका

ब्रिटेन

भारत 2023 INDIA

भारत की जी20 की अध्यक्षता: सोशल मीडिया कवरेज

https://www.g20.org

https://twitter.com/g20org

https://www.facebook.com/g20org

https://www.instagram.com/g20org/?hl=en

https://www.youtube.com/channel/UCspVYmJSYUek633_enhLo3w

इस दस्तावेज़ और पिछली जी20 और टी–20 विज्ञप्तियों को एक्सेस करने के लिए क्लिक करें:

https://bit.ly/3UiAa9s

स्कैन **QR code**

Images Credit: pixabay.com